भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1112

26 जुलाई, 2023 के लिए प्रश्न

गेहूं की कीमतों का रूझान

1112. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की मंडियों में गेहूं की कीमतों का मौजूदा उच्च रुझान इस बात का संकेत है कि सरकार लक्षित गेहूं खरीद कैसे करेगी क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य मंडी मूल्य से लगभग 200-300 रुपये प्रति क्विंटल कम है;

(ख) क्या 2022 में निर्धारित लक्ष्य से कम खरीद का कारण मंडी दरों की तुलना में गेहूं का कम न्यूनतम समर्थन मूल्य था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2023-24 के दौरान गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): आरएमएस 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद दिनांक 15.03.2023 को शुरू हुई थी और दिनांक 30.06.2023 तक जारी रही। आरएमएस 2023-24 के दौरान एमएसपी पर 262.02 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है, जो आरएमएस 2022-23 के दौरान खरीदे गए 187.92 लाख टन से 39.43% अधिक है।

दिनांक 01.07.2023 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की स्टॉक स्थिति 275.80 लाख टन के बफर मानदंडों की तुलना में 301.45 लाख टन है। यह स्पष्ट है कि गेहूं का स्टॉक स्तर बफर मानदंडों की आवश्यकता से काफी ऊपर है।

(ख) और (ग): पिछले वर्ष आरएमएस 2022-23 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद 187.92 लाख टन थी। गर्मी के पूर्व आगमन और भू-राजनीतिक स्थिति के कारण, गेहूं की वैश्विक कीमतों में वृद्धि हुई थी। तथापि, देश भर के किसानों को ऊँची बाज़ार दरों से लाभ हुआ था, क्योंकि अधिकांश किसानों ने अपनी उपज ऊँची बाज़ार दरों पर निजी व्यापारियों को बेच दी थी।

(घ): गेहूं का एमएसपी आरएमएस 2022-23 के लिए 2015 रुपये प्रति क्विंटल से 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर आरएमएस 2023-24 के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

*****